10. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
11. ग्रामीण अन्न बैंक।
12. विस्थापित जनजातीय परिवारों का पुनर्वास।
13. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान।
14. सूक्ष्म वन उत्पादन प्रचालनों के लिए राज्य आदिवासी सहकारी निगमों को सहायता अनुदान।
15. अनुसंधान और प्रशिक्षण।

3. अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं

1. आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम।
3. अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करना।
4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम।
5. मदरसा और मकताब का आधुनिकीकरण।
6. समुदाय पोलीटेकनीक की योजना।
7. केन्द्रीय वक्फ परिसर और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को क्रमशः सामान्य रूप से अन्यों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं और शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास की उनकी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान।

Permanent Office for Dr. Ambedkar Foundation

2112. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Dr. Ambedkar Foundation has sought permanent allotment of Bungalow No. 25, Ashoka Road, New Delhi for housing the office of Dr. Ambedkar Foundation as requested by its Governing Body on 14th September, 1997;

(b) if so, what action has been taken in this regard; and

(c) what arrangement has been made for providing a permanent office to Dr. Ambedkar Foundation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Matter has been taken with the M/O Urban Affairs and Employment for permanent allotment for the Office of Dr. Ambedkar Foundation.

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं

2113. **श्रीमती मालती शर्मा:**
प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये बहुत सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कितनी राशि जारी की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि खर्च किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) जी, हां। देश में और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही है। केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ख) से (घ) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।